भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1116
दिनांक 08.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

ताइवान के साथ समझौता

1116. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री प्रतापराव जाधवः
श्री श्रीरंग अप्पा बारणे:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ताइवान ने पूरे ताइवान मे विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 1 लाख भारतीयों को रोजगार देने में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने ताइवान सरकार के साथ किसी रोजगार समझौते/करार पर हस्ताक्षर किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो विदेशो में भारतीय कामगारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उक्त रोजगार समझौते पर कब तक हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है;

(ङ) इस प्रकार के समझौते/करार से दोनों राष्ट्रों के बीच आपसी सबंध किस प्रकार सुदृढ़ होंगे; और

(च) क्या सरकार ने विश्व के अन्य देशों के साथ उक्त रोजगार समझौता/करार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) से (ङ) सरकार ताइवान के साथ व्यापार, निवेश, पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा और इसी प्रकार के लोगों के मध्य आदान–प्रदान के अन्य क्षेत्रों में पारस्परिक संपर्क को सुविधाजनक बनाती है और बढ़ावा देती है। सरकार पारस्परिक हित के आधार पर विदेशों में भारतीय कामगारों को कानूनी रोजगार की सुविधा भी प्रदान करती है।

(च) श्रम एवं जनशक्ति सहयोग समझौता ज्ञापन/करार जो श्रम एवं जनशक्ति से संबंधित मुद्दों पर सहयोग के लिए व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, उन पर खाड़ी सहयोग परिषद के देशों (बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात) और जॉर्डन के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जीसीसी देशों में घरेलू कामगारों के विशिष्ट हितों की रक्षा के लिए सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत के साथ घरेलू क्षेत्र के लिए श्रम सहयोग संबंधी करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। डेनमार्क, जापान, पुर्तगाल, मॉरीशस और इज़राइल के साथ विशिष्ट श्रम आवाजाही सहभागिता करारों/समझौता ज्ञापनों/सहयोग ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हमारे छात्रों, शिक्षाविदों, व्यापारियों और पेशेवरों के लिए आवाजाही की सुविधा हेतु फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया और इटली के साथ प्रवासन एवं आवाजाही सहभागिता करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

*****